University Education

903. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that State Governments are unable to meet the need of people for university education;

(b) whether it is a fact that a large number of students are unable to get university education in rural areas and small towns;

(c) whether Government have contemplated any new and innovative concepts to meet the present day demands of State Sector University education; and

(d) if so, the details of the concepts under cosideration?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (d) While it is difficult to generalise that the aspirations of a number of young persons to receive University education are unfulfilled, it is possible that the continued increase in population may be responsible for demands in certain areas.

The policy relating to extension of Distance Education System, both through open and conventional universities, and provision of non-collegiate educational system are the initiatives introduced to meet the aspirations of all to receive tertiary education.

रेलवे की केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों और राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया देय-राशि

904. **श्री अजीत जोगी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय केन्द्रीय विद्युत स्टेशनों और राज्य विद्युत बोर्डों की ओर भारतीय रेलवे की करोड़ों रुपये की धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने काफी समय से बकाया पड़ी धनराशि की वसूली के लिए इस वर्ष के दौरान इन विद्युत स्टेशनों और विद्युत बोर्डों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया है;

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे ने इस संबंध में कुछ विकल्पों का सुझाव दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी हां।

(ख) 30.9.96 को परियोजनावार विवरण:-

क्रम सं॰	राज्य विद्युत बोर्ड/ पावर हाउस का नाम	(करोड़ रु. में)
1.	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	29.97
2.	असम राज्य विद्युत बोर्ड	6.91
3.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	3.94
4.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	86.31
5.	गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड	10.86
6.	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	71.00
7.	कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड	0.07
8.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	31.35
9.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	4.14
10.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	37.97
11.	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	1.19
12.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	1.29
13.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	47.58
14.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	29.28
15.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम/बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र	711.12
16.	राष्ट्रीय ताप विद्युत नि.लि./अन्य	50.85
17.	प्राइवेट पावर हाउस – साबरमती	2.54
	जोड़ :	1126.37

(ग) जी, हां।

(घ) मंत्रि मंडल ने विनिश्चय किया है कि नई राशि देय होने को रोकने के उद्देश्य से सभी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत गृहों पर 1.10.96 से अदायगी योजना लागू की जानी चाहिए। यह योजना बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र के संबंध में 31.12.96 तक अस्थायी रूप से आस्थगित कर दी गई है। पिछली बकाया राशि की वापसी के संबंध में मंत्रिमंड़ल की उपयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय के